भारत की विकास दर 7 .4 प्रतिशत

फिच का अनुमान- भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था से आगे

मजबूत कंजम्शन और जीएसटी सुधार से ग्रोथ तेज

नई दिल्ली, 4 दिसंबर. फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान को 6.9 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.4 प्रतिशत कर दिया है. एजेंसी ने घरेलू कंजम्शन, व्यापक जीएसटी सुधार और घटती महंगाई को विकास दर बढ़ाने वाले मुख्य कारक बताया.

जुलाई-सितंबर तिमाही में जीडीपी 8.2प्रतिशत तक पहुंच गई, जो पहली तिमाही की 7.8त्न वृद्धि से अधिक है. फिच के अनुसार निजी खपत, सेवाओं का विस्तार और निवेश में सुधार से भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक स्तर पर मजबूत बनी रहेगी. एजेंसी ने वाई 27 के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.4 प्रतिशत रखने का अनुमान जताया है. देश की मजबूत आर्थिक गतिविधियों और सकारात्मक बाजार संकेतों के साथ जोड़ा है. क्यू 2 में जीडीपी ग्रोथ 8.2त्न दर्ज की गई, जो पहली तिमाही की 7.8त्न वृद्धि से भी बेहतर है. फिच का मानना है कि कंजम्शन इस साल विकास का सबसे बड़ा इंजन बना रहेगा. मजबूत आय वृद्धि, उपभोक्ता भावनाओं में सुधार और 375 वस्तुओं पर लागू व्यापक जीएसटी कटौती ने घरेलू मांग को तेजी दी है.

फिच ने मुद्रास्फीति में गिरावट को भी सकारात्मक बताया. अक्टूबर में रिटेल महंगाई दर सिर्फ 0.3त्न रही, जिससे उपभोक्ता क्रय शक्ति बढ़ी और खर्च में तेजी आई. कम महंगाई के कारण भारतीय रिजर्व बैंक को ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश मिली है. फिच का अनुमान है कि दिसंबर में आरबीआई रेपो रेट 5.25प्रतिशत तक घटा सकता है.

इसके अलावा, एफवाई 27 की दूसरी छमाही में निजी निवेश में तेजी लौटने की उम्मीद जताई गई है. फाइनेंशियल कंडीशंस के सुधरने और कर्ज की लागत कम होने के बाद भारत में कैपिटल एक्सपेंडिचर की गति बढ़ सकती है. फिच का निष्कर्ष है कि भारत की आर्थिक वृद्धि विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में मजबूत बनी रहेगी.

आईआरसीटीसी ने लॉन्च किए चार खास अंडमान टूर पैकेज

नई दिल्ली, 04 दिसंबर. नया साल 2026 करीब आते ही यात्राओं की रफ्तार तेज हो गई है और इसी के बीच आईआरसीटीसी ने अंडमान के लिए चार खास टूर पैकेज पेश किए हैं. अंडमान, सर्दियों में घूमने वालों की पहली पसंद बन जाता है. आईआरसीटीसी के ये पैकेज पहली बार घूमने वालों से लेकर एडवेंचर पसंद यात्रियों, फैमिली टूर और कपल्स—सभी के लिए तैयार किए गए हैं. एग्जोटिक अंडमान पैकेज सबसे सस्ता है, वहीं रोमांटिक अंडमान पैकेज सबसे प्रीमियम अनुभव देता है. इन चारों विकल्पों की तुलना से साफ होता है कि अलग-अलग जरूरतों और बजट वाले यात्रियों के लिए आईआरसीटीसी ने नए साल पर एक बेहतरीन रेंज उपलब्ध कराई है.

ईवी बाजार 2030 तक 20 लाख करोड़

गडकरी बोले... पांच करोड़ रोजगार होंगे सृजित

दोपहिया और तिपहिया ईवी बिक्री में रफ्तार

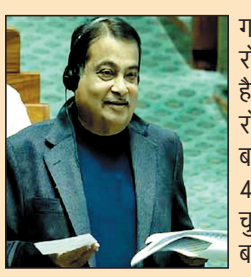

गडकरी ने कहा कि ईवी क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. अनुमान है कि इस विकास से पांच करोड़ नए रोजगार सृजित होंगे. उन्होंने यह भी बताया कि दोपहिया ईवी बाजार में 400 से अधिक स्टार्ट-अप शुरू हो चुके हैं और 2024 से यह 21 प्रतिशत बढ़े हैं.

नई दिल्ली, 4 दिसंबर. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को संसद में बड़ा दावा किया कि भारत का इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बाजार 2030 तक 20 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. गडकरी ने कहा कि इससे पाँच करोड़ नए रोजगार पैदा होंगे और देश ऊर्जा निर्यातक बन सकेगा.

वर्तमान में भारत में 57 लाख ईवी पंजीकृत हैं और 2024-25 में बिक्री में तेजी आई है. उन्होंने दोपहिया और तिपहिया ईवी की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि और जम्मू-कश्मीर में पाए गए लिथियम भंडार का जिक्र करते हुए कहा कि यह देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में स्पष्ट किया कि भारत का इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बाजार 2030 तक 20 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की क्षमता रखता है. उन्होंने बताया कि वर्तमान में देश में 57 लाख ईवी पंजीकृत हैं और 2024-25 में बिक्री में तेजी देखी गई. ईवी कार की बिक्री में 20.8 प्रतिशत, दोपहिया वाहनों में 33 प्रतिशत और तिपहिया वाहनों में 18 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई. इसके विपरीत पेट्रोल और डीजल वाहनों की बिक्री में मामूली वृद्धि ही रही.

लिथियम-आयन बैटरी की कीमत घटकर 55 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोवाट-घंटा हो गई है, जिससे उत्पादन लागत कम होगी. जम्मू-कश्मीर में 60 लाख टन लिथियम भंडार पाया गया है, जो दुनिया के कुल भंडार का 6 प्रतिशत है.

मंत्री गोयल ने विनिर्माण उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने पर दिया जोर

वैश्विक विकास के प्रति संवेदनशील बने रहने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला

नयी दिल्ली, 04 नवंबर. वाणिज्य एवं उद्योगमंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को भारत की विनिर्माण उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए नवाचार, गुणवत्ता, डिजाइन, स्थिरता तथा दक्षता को बढ़ाने पर बल दिया और कहा कि सरकार इसके लिए पूरा नीतिगत सहयोग कर रही है.

पीयूष गोयल ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा विनिर्माण क्षेत्र पर केंद्रित कार्यक्रम इंडियाएज को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार देश की आर्थिक प्रगति में सहयोग के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण के साथ काम कर रही है. उन्होंने कृषि, सेवा और विनिर्माण क्षेत्र में हाल के विकास रुझानों का उल्लेख किया और बताया कि भारत का विनिर्माण उत्पादन इलेक्ट्रॉनिक्स, श्वेत वस्तुओं, रसायनों और पेट्रोकेमिकल्स जैसे नए क्षेत्रों में विविधता पूर्ण हो गया है. उन्होंने उद्योग जगत के लिए प्रतिस्पर्धी बने रहने और वैश्विक विकास के प्रति संवेदनशील बने रहने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और कहा कि हाल में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आये व्यवधानों ने देश की आपूर्ति श्रृंखला को सुदृ? करने के महत्व को रेखांकित किया है. उन्होंने कहा कि इन व्यवधानों से आपूर्ति के लिए कुछ एक देशों या क्षेत्रों पर अत्यधिक निर्भरता से जुड़े जोखिम भी सामने आये हैं. उन्होंने उन क्षेत्रों की पहचान करने की आवश्यकता पर बल दिया जहाँ घरेलू क्षमता और आपूर्ति श्रृंखलाओं पर अधिक नियंत्रण आवश्यक है.

पीयूष गोयल ने कहा कि विनिर्माण उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्योग जगत के साथ सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है और उन्होंने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि से सेवाओं के क्षेत्र में वृद्धि को और गति मिलेगी. उन्होंने आगे कहा कि जैसे-जैसे भारत वैश्विक बाजारों में अपनी उपस्थिति मजबूत कर रहा है, उसे घरेलू अर्थव्यवस्था में भी प्रतिस्पर्धी प्रथाओं के लिए खुला रहना होगा.

वाणिज्य मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश और ओडिशा सहित कई राज्यों ने हाल के वर्षों में तेजी से प्रगति की है, जिसके परिणामस्वरूप स्थानीय अवसरों में वृद्धि हुई है और प्रवासन में कमी आई है. उन्होंने उद्योग जगत को प्रक्रियाओं को सरल बनाने, नियामक प्रणालियों में सुधार लाने और विनिर्माण वातावरण को मज़बूत बनाने के लिए सुझाव देने के लिए प्रोत्साहित किया.

तस्करी रोकने के लिए किए जा रहे कड़े उपाय

नई दिल्ली, 04 दिसबंर. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ईमानदार करदाताओं को गरिमा और सुरक्षा के साथ व्यापार करने के अवसर सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है, लेकिन तस्करी और अवैध व्यापार को लेकर किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य भारत की भूमि, जलमार्ग और वायुमार्ग से अवैध गतिविधियों के हर संभावित रास्ते को पूरी तरह बंद कर देना है. राजधानी में राजस्व आसूचना निदेशालय के 68वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करते हुए उन्होंने डीआरआई की भूमिका की सराहना की. उन्होंने कहा कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए डीआरआई ने अद्भुत क्षमता, प्रतिबद्धता और दक्षता का प्रदर्शन किया है.

सोने चांदी के दाम में गिरावट

459 रुपए कम हुआ सोना

2,477 रुपए सस्ती हुई चांदी

नई दिल्ली, 04 दिसबंर. सोने-चांदी के दाम में गुरुवार को गिरावट देखी गई. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम सोना 459 रुपए सस्ता होकर 1,27,755 रुपए पर आ गया. वहीं, चांदी का दाम 2,477 रुपए घटकर 1,75,713 रुपए प्रति किलो हो गया.

इस साल अब तक सोने की कीमत 51,593 रुपए और चांदी की 89,696 रुपए बढ़ चुकी है. केंद्रीय बैंकों की खरीदारी, क्रिप्टो और शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव, तथा शादियों और निवेश की बढ़ती मांग सोने की कीमतों को मजबूती दे रही है. एक्सपर्ट के अनुसार इस साल सोना 1,35,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है.

गुरुवार को सोने-चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम सोना 459 रुपए घटकर 1,27,755 रुपए पर आ गया. चांदी का भाव 2,477 रुपए फिसलकर 1,75,713 रुपए प्रति किलो हुआ.

जीडीपी आंकड़े होंगे और सटीक

वित्त मंत्री ने बताया नया आधार 2022-23 बेस ईयर

पुराने बेस ईयर की कमी दूर होगी

नई दिल्ली, 04 दिसबंर. सरकार 27 फरवरी से जीडीपी के बेस ईयर को 2011-12 से बदलकर 2022-23 करने जा रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया कि यह कदम देश की आर्थिक गतिविधियों को वर्तमान परिदृश्य के अनुसार और सटीक दिखाने के लिए लिया जा रहा है.

पुराने डेटा में कुछ कमियां थीं, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत मिलने वाले अनाज पर खर्च न दिखाना. नया बेस ईयर नैशनल अकाउंट्स को और भरोसेमंद बनाएगा और रियल जीडीपी वृद्धि की सही तस्वीर पेश करेगा. इससे बजट और नीति निर्माण में भी अधिक सटीकता आएगी.

वर्तमान में देश के लिए 2011-12 को बेस ईयर के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जो एक दशक से अधिक पुराना हो चुका है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बताया कि नया बेस ईयर देश की मौजूदा आर्थिक गतिविधियों को अधिक सटीक रूप से दिखाने में मदद करेगा.

बेस ईयर अपडेट करने से नैशनल अकाउंट्स की गुणवत्ता बेहतर होगी और डेटा आधुनिक अर्थव्यवस्था की वास्तविकता के अनुरूप आएगा. पुराने बेस ईयर के कारण जीएसटी की रिपोर्ट में भारत को ग्रेड मिला था, हालांकि यह डेटा की गुणवत्ता पर आधारित नहीं बल्कि पुराने आधार पर था. नया बेस ईयर बजट और नीति निर्माण में भी मददगार होगा, क्योंकि इससे जीडीपी वृद्धि, महंगाई और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को अधिक सही तरीके से मापा जा सकेगा. इस बदलाव से कुछ खास कमियां भी दूर होंगी, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत मिलने वाले अनाज पर खर्च पहले नहीं दिखाया जाता था.

मुकेश अंबानी लाएंगे अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ

नई दिल्ली, 04 दिसबंर. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपनी डिजिटल सेवाओं वाली कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की तैयारी तेज कर चुकी है.

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ने जियो के लिए शुरुआती ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस तैयार करने पर काम शुरू कर दिया है. यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब जियो 500 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स के साथ भारत की सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी बन चुकी है.

रिलायंस बैंकर्स के साथ बातचीत कर रही है ताकि ड्राफ्ट प्रॉस्पेक्टस को जल्द से जल्द सेबी के पास फाइल किया जा सके. सेबी ने हाल में बड़े आईपीओ के लिए न्यूनतम हिस्सेदारी बिक्री को 2.5त्न तक घटाया है, और इसी नियम के लागू होते ही प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.

4 दिन बाद सेंसेक्स-निफ्टी बढ़त पर

आईटी और रियल्टी शेयर चमके

मिडकैप-स्मॉलकैप इंडेक्स फ्लैट बंद

मुंबई, 04 दिसबंर. चार दिन की गिरावट के बाद भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार को मजबूती दिखाई. कारोबार के अंत में सेंसेक्स 158.51 अंक यानी 0.19 प्रतिशत की बढ़त के साथ 85,265.32 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 47.75 अंक यानी 0.18 प्रतिशत की बढ़त के साथ 26,033.75 पर बंद हुआ.

आईटी और रियल्टी सेक्टर के शेयर निवेशकों का आकर्षण बने रहे. मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स की चाल आज फ्लैट रही. वहीं, फिनटेक कंपनी में 75 करोड़ तक निवेश और अधिग्रहण को मंजूरी दी, जो कंपनी की सेवाओं के विस्तार की दिशा में रणनीतिक कदम है.

चार दिनों की गिरावट के बाद गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार में मजबूती देखी गई. सेंसेक्स कारोबार के अंत में 158.51 अंक यानी 0.19 प्रतिशत की बढ़त के साथ 85,265.32 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 47.75 अंक यानी 0.18 प्रतिशत की बढ़त के साथ 26,033.75 के स्तर पर बंद हुआ. यह वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में हल्की मजबूती का संकेत है. आईटी और रियल्टी सेक्टर के शेयरों में खरीदारी रही, जबकि मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स की चाल फ्लैट रही.

चावल, गेहूं, दालें नरम चीनी मजबूत

नयी दिल्ली, 04 दिसंबर. घरेलू थोक जिंस बाजारों में बुधवार को चावल के औसत भाव घट गये. गेहूं और दालों में भी गिरावट रही जबकि चीनी के भाव बढ़ गये. खाद्य तेलों में उतार-चढ़ाव देखा गया. औसत दर्जे के चावल की औसत कीमत 11 रुपये घटकर 3,842.17 रुपये प्रति क्विंटल रह गयी. गेहूं 12 रुपये सस्ता हुआ और 2,841.35 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गया. आटा पांच रुपये प्रति क्विंटल नरम हुआ. दाल-दलहनों में नरमी रही. तुअर दाल और उड़द दाल 19-19 रुपये प्रति क्विंटल टूट गयी.

समाचार विशेष

लालू परिवार सजा की संभावना से परेशान

जमीन के बदले नौकरी और आईआरसीटीसी टेंडर से जुड़े मामलों में आरोप तय

पटना. बिहार विधानसभा का चुनाव बुरी तरह से हारने के बाद अब लालू प्रसाद का परिवार कानूनी मामलों को लेकर चिंता में है. एक तरफ परिवार पूरी तरह से विभाजित है और कलह बढ़ा हुआ है तो दूसरी ओर ऐसा लग रहा है कि रेलवे से जुड़े दोनों मामलों की सुनवाई पूरी हुई तो सजा हो जाएगी.

तभी पूरा परिवार किसी तरह से सुनवाई टालने या उसमें देरी कराने के प्रयास में लगा हुआ है ताकि समय मिले तो प्रबंधन के उपाय हों. लेकिन अभी कोई उपाय नहीं दिख रहा है. पार्टी और परिवार के एक करीबी जानकार ने कहा कि लालू प्रसाद इस बात से परेशान हैं कि उनकी आंखों के सामने परिवार के दूसरे सदस्यों को जेल जाना पड़ सकता है. यह भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव इस बात से बहुत नाराज रहते हैं कि लालू प्रसाद के कार्यकाल की गड़बड़ियों की कीमत वे राजनीतिक रूप से चुका रहे हैं और कानूनी रूप से भी चुकानी पड़ सकती है.

गौरतलब है कि लालू प्रसाद चारा घोटाले से जुड़े तीन मामलों में दोषी ठहराए जा चुके हैं. अभी उसमें दो मामले और बचे हैं.

ध्यान रहे इससे पहले बिहार चुनाव के दौरान लालू प्रसाद अदालत पहुंचे थे और उन्होंने याचिका देकर रेलवे से जुड़े मामलों की रोजाना सुनवाई रोकने को कहा था. उनका कहना था कि रोजाना सुनवाई नहीं होनी चाहिए. लेकिन अदालत ने उनकी अपील खारिज कर दी. लालू प्रसाद की याचिका भी मामले में देरी कराने के मकसद से दी गई थी.

विपक्ष के नेताओं को थामना मुश्किल

मुंबई. वैसे तो यह पूरे देश की परिघटना है लेकिन महाराष्ट्र में गजब हुआ है. पिछले चुनाव में यानी 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे महाविकास अघाड़ी की तीन पार्टियों के 43 उम्मीदवारों ने एक साल में पाला बदल लिया है.

महाविकास अघाड़ी के ये उम्मीदवार महायुति यानी भाजपा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल हो गए हैं. सोचें, ये उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे इसका मतलब है कि अपने आप ये अपने क्षेत्र के शैडो विधायक थे. इनमें से कुछ उम्मीदवार तो बहुत कम अंतर से हारे थे और हो सकता है कि अगली बार चुनाव में जीत जाते. लेकिन उन्होंने पांच साल तक विपक्ष में रह कर इंतजार करने और जमीन पर काम करने की बजाय सत्ता के साथ चले गए. इतना ही नहीं दूसरे स्थान पर रहे तीन निर्दलीय भी महायुति के साथ चले गए. पाला बदलने वाले नेताओं में से सबसे ज्यादा उद्धव ठाकरे की शिव सेना के हैं. उनकी पार्टी के 19 ऐसे उम्मीदवार जो पिछले चुनाव में दूसरे स्थान पर रहे थे पाला बदल कर सत्तारूढ़ गठबंधन में चले गए हैं.

नंबर गेम में जेडीयू पर भारी पड़ी बीजेपी

पटना. बिहार में नवगठित नीतीश कुमार कैबिनेट में भाजपा के सबसे ज्यादा मंत्री शामिल हैं, लेकिन बजट और मलाईदार विभागों के मामले में जदयू ने स्पष्ट बढ़त हासिल की है. राज्य सरकार के कुल 3,16,895.02 करोड़ रुपये के वार्षिक बजट में जदयू के पास लगभग 65.73 फीसदी का हिस्सा है, जबकि भाजपा के 14 मंत्रियों के पास केवल 29.22 फीसदी बजट वाले विभाग हैं.

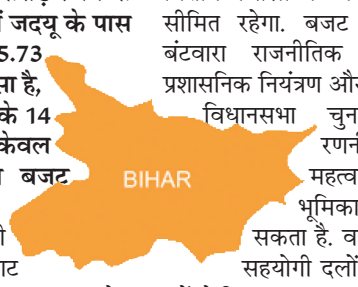

उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी के पास 17,831.21 करोड़ रुपये का गृह विभाग है, जबकि भाजपा के स्वास्थ्य एवं विधि मंत्री मंगल पांडेय को 20,035.80 करोड़ रुपये का स्वास्थ्य विभाग मिला. जदयू के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को सबसे बड़ा बजट वाला विभाग शिक्षा (60,964.87 करोड़ रुपये) मिला है, जो कैबिनेट में सबसे बड़ी राशि है.

छोटे सहयोगी दलों जैसे रालोमो, हम और लोजपा को भी सीमित बजट वाले विभाग मिले हैं. यह वितरण राज्य में जदयू की शक्ति और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नियंत्रण को दर्शाता है. भाजपा के पास मंत्री संख्या ज्यादा होने के बावजूद प्रमुख विकास और वित्तीय फैसलों में उनका प्रभाव सीमित रहेगा. बजट का यह बंटवारा राजनीतिक संतुलन, प्रशासनिक नियंत्रण और आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. वहीं, छोटे सहयोगी दलों की बात करें तो चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास) के दो मंत्री को कुल बजट का 0.91 प्रतिशत, जीतनराम मांझी की हम पार्टी के एक मंत्री को 0.58 प्रतिशत, और उपेंद्र कुशवाहा की रालोमो के एक मंत्री को 3.56 प्रतिशत बजट वाले विभाग मिले हैं. इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के अन्य मंत्रियों के पास कुल बजट का बड़ा हिस्सा है.

बजट में भाजपा का हिस्सा केवल एक चौथाई

अन्य विभागों में श्रेयसी सिंह को सूचना प्राविधिकी (289 .03 करोड़ रुपये) और खेल (248 .39 करोड़ रुपये), डॉ. प्रमोद कुमार को सहकारिता (1,231 .92 करोड़ रुपये) और पर्यावरण एवं वन (906 .89 करोड़ रुपये), संजय पासवान को गन्ना उद्योग (192 .26 करोड़ रुपये), संजय कुमार सिंह को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण (2,702 .63 करोड़ रुपये) और संतोष कुमार सुमन को लघु जल संसाधन (1,839 .11 करोड़ रुपये) शामिल हैं. भले ही भाजपा के पास ज्यादा मंत्री हों, लेकिन कुल बजट में उनका हिस्सा केवल एक चौथाई ही है.

विशेष — ओबीसी जातियों पर खेला दांव, मायने कितने गहरे?

यूपी में भाजपा की तस्वीर साफ

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है, लेकिन इससे पहले बीजेपी ने अपने 14 जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है. बुधवार देर रात जारी की गई लिस्ट में 14 जिलाध्यक्षों के नाम घोषित किए गए हैं.

बीजेपी दो साल से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी तलाश कर रही है. मगर, राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम के ऐलान से पहले ही यूपी में बीजेपी ने संगठन में बदलाव की शुरुआत कर दी है. 14 जिलाध्यक्ष के नामों का ऐलान प्रदेश चुनाव अधिकारी और पूर्व केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने किया.

दरअसल, पार्टी ने जिलाध्यक्षों का जिले स्तर पर चुनाव करवाया था. 14 नामों के ऐलान के बाद माना जा रहा है कि बाकी के जिलों में भी जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों की घोषणा कर दी जाएगी. इस प्रक्रिया के पूरे होने के बाद ही यूपी में प्रदेश अध्यक्ष का चयन किया जाएगा. मगर, बीजेपी ने जिन 14 नेताओं को जिला अध्यक्ष बनाया है, इसके मायने दूर तक जाते हैं. पार्टी ने यह कदम बहुत सोच समझकर उठाया है.

जिलाध्यक्ष के नाम दिलचस्प

बुधवार को जारी की गई बीजेपी जिलाध्यक्ष के नाम दिलचस्प है. इस लिस्ट में ही यूपी की राजनीति के मायने छुपे हुए हैं. दरअसल, इस लिस्ट की एक खास बात ये है कि बीजेपी जिलाध्यक्ष के नामों के आगे उनकी जाति भी लिखी गई है. नामों के आगे सामान्य, पिछड़ा, अनुसूचित जाति लिखकर पार्टी ने नामों की घोषणा की है. जिन 14 जिलों के जिलाध्यक्ष के नाम की घोषणा की गई है, उनमें 7 में सामान्य वर्ग से जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, जबकि 6 पिछड़ा (ओबीसी) और एक अनुसूचित जाति वर्ग से हैं. बीजेपी केंद्र से लेकर राज्यों में... खासतौर से उत्तर भारत में पिछड़ों औक दलितों की सियासत कर रही है. ऐसे में पार्टी इस वर्ग की जातियों को साधने के लिए इसी वर्ग के नेताओं को महत्व दे रही है. क्योंकि उत्तर प्रदेश से संदेश दिल्ली तक जाता है, इसलिए पार्टी ने नामों के आगे जाति लिखकर संदेश देने की कोशिश की है.

नियुक्ति के असल मायने

दरअसल, बीजेपी ने जिन छह जिलों में ओबीसी जातियों के नेताओं को जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी, इन जिलों में बीजेपी को 2024 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, या फिर पार्टी बहुत कम मार्जिन से चुनाव जीतने में सफल हुई थी. बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में हमीरपुर (समाजवादी पार्टी), जौनपुर (समाजवादी पार्टी), कौशाम्बी (समाजवादी पार्टी), बाराबंकी (कांग्रेस) से हार गई थी. वहीं, मेरठ में पार्टी महज लगभग 12 हजार वोटों से जीती थी. हालांकि हाथरस में बीजेपी बड़े मार्जिन से जीती थी. हमीरपुर, जौनपुर, कौशाम्बी और बाराबंकी में समाजवादी पार्टी ने ओबीसी जातियों को एकजुट करके और पीडीए का नारा देकर साधा, जिससे उसे जनता ने पिछले लोकसभा में आशीर्वाद दिया. पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों के भरोसे ही सपा यूपी में अकेले 37 जीतने में कामयाब रही. मेरठ में बीजेपी सांसद अरुण गोविल सामाजवादी पार्टी की सुनीता वर्मा से हारते-हारते बचे थे. ऐसे में यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में प्रस्तावित हैं. बीजेपी आगामी चुनाव में 2024 की गलती या फिर किसी भी तरह की कमी को दूर करने में जी-जीन से जुटी है.